शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 03 - 10 अप्रैल 2023 मूल्य पांच रूपए

सुक्खू सरकार की पहली चुनावी परीक्षा होगी नगर निगम शिमला के चुनाव

अराजकता का पर्याय बन चुका है नगर निगम
सत्ता परिवर्तन का कोई असर नहीं हुआ प्रशासन पर
एन.जी.टी. के फैसले पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा चुनाव में उतरने से पहले

शिमला/शैल। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद होने जा रहे नगर निगम शिमला के चुनाव सुक्खू सरकार की पहली चुनावी परीक्षा होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के लिये यह और भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है कि वह इसी नगर निगम से दो बार छोटा शिमला वार्ड से पार्षद रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी इसी शहर में हुई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद होने जा रहा यह चुनाव उनकी सरकार के लिये भी किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। क्योंकि शिमला को मिनी हिमाचल की संज्ञा भी हासिल है। प्रदेश के हर भाग का आदमी शिमला में मिल जाता है। फिर यह नगर निगम क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। इस नाते यह चुनाव सुक्खू सरकार द्वारा चार माह में लिये गये फैसलों का भी आकलन होगा। सुक्खू सरकार ने यह घोषित कर रखा है कि वह व्यवस्था परिवर्तन करने आयी है और इसी व्यवस्था परिवर्तन के तहत शिमला नगर निगम के आयुक्त और संयुक्त आयुक्त नहीं बदले गये हैं। इस निगम के चुनाव पिछले वर्ष होने थे जो कुछ कारणों से नहीं हो पाये और आज यह प्रशासक के अधीन चल रही है। प्रशासक का दायित्व जिलाधीश शिमला के पास है और वह भी नहीं बदले गये हैं। पुराने प्रशासन के साये में ही यह चुनाव हो रहे हैं। नगर निगम के वार्ड 34 हो या 41 इस संबंध में भाजपा की एक याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है । बल्कि इस पर फैसला सुरक्षित है जो कभी भी घोषित हो सकता है। उस फैसले का असर भी निगम चुनावों के परिणाम पर पड़ेगा। यदि वार्ड 41 हो जाते हैं तो इसका कुछ लाभ वामदलों को भी मिलेगा। इस बार आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप के रिश्ते कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी पर हैं। इसका असर दोनों कांग्रेस और भाजपा पर एक बराबर पड़ेगा। अभी जो वार्डों को लेकर रोस्टर जारी हुआ है उसमें कांग्रेस की गुटबन्दी ज्यादा चर्चा में है।

इस सबसे हटकर यदि राजनीतिक आकलन किया जाये तो इस समय मंत्रिमंडल और अन्य राजनीतिक ताजपोशी की बात की जाये तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जिला शिमला का है। यह इसलिये हुआ कहा जा रहा है कि सुक्खू की कार्यस्थली ही शिमला रही है। कई ऐसे लोगों की ताजपोशियां भी शायद हो गयी हैं जो शायद कांग्रेस संगठन में भी कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं थे। शिमला में ही कई वरिष्ठ कार्यकर्ता नजरअंदाज हो गये हैं जिनकी निष्ठा शायद हॉलीलाज के साथ थी। जितना प्रतिनिधित्व जिला शिमला को दे दिया गया है उतना किसी भी अन्य जिले को मिल पाना अब संभव नहीं रह गया है और देर सवेर यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा यह तय है। इसलिए यह राजनीतिक असंतुलन यदि कहीं नगर निगम चुनावों में चर्चित हो गया तो निश्चित रूप से संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि गारंटीयां देकर सत्ता में आयी सरकार अभी तक व्यवहारिक तौर पर जनता को कोई राहत नहीं दे पायी है। बल्कि आते ही तीन रूपये प्रति लीटर डीजल के दामों में बढ़ौतरी कर दी गयी। अब बिजली की दरें 22 से 46 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गयी हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिये शक्तियां ही नही दे पायी हैं। क्या सुक्खू सरकार कैग की सिफारिशों के अनुरूप कदम उठाने का वायदा करेगी।

शिमला नगर निगम प्रशासन एक तरह से अराजकता का पर्याय बना हुआ है यहां पर अदालती फैसलों पर अमल करने या उनके खिलाफ अगली अदालत में अपील करने की बजाये फैसलों पर पार्षदों की कमेटियां राय बनाकर लोगों को परेशान करती है। एन.जी.टी. के फैसले को नजरअंदाज करके शहर में कितने निर्माण खड़े हो गये हैं यह अराजकता का ही परिणाम है। शिमला जल प्रबन्धन निगम रिटायरियों की शरण स्थली बनकर रह गयी है वहां पर सुक्खू सरकार के आदेश भी लागू नहीं हो पाये हैं। स्मार्ट सिटी के तहत कितने निर्माण बनने की स्टेज पर ही गिर गये और किसी की कोई जिम्मेदारी तय नही हो पायी। अब चुनावों के दौरान ऐसे दर्जनों मामले जवाब मांगेंगे। क्योंकि निगम प्रशासन में सत्ता परिवर्तन की कोई झलक देखने को नहीं मिली है।

निगम चुनावों पर गंभीर है भाजपा के आरोप

शिमला/शैल। । प्रदेश भाजपा ने अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में राज्य चुनाव आयुक्त को नगर निगम शिमला के लिये कांग्रेस द्वारा फर्जी वोट बनाये जाने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा गया है कि एक घर में 18 से 20 वोट बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा उपमुख्यमंत्री और कुछ अन्य मंत्रीयों के घरों में हो रहा है। आरोप लगाया गया है कि वैनमोर में एक ही कमरे में 18 से 20 लोगों ने वोट बनाने के लिये आवेदन किया है और भी कई वार्डों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। निगम चंनावों के लिये जारी किये गये रोस्टर को तैयार करने में भी पक्षपात का आरोप लगाया गया है। भाजपा के यह आरोप गंभीर है और इन चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बनेंगे यह तय है। राज्य निर्वाचन आयोग और संबद्ध प्रशासन कि इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। निवर्तमान निगम सदन में भाजपा का बहुमत था। सी.पी.एम. और कांग्रेस के कुछ पार्षट भी पासा बदलकर भाजपा में शामिल हो गये थे। इस समय निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और अन्य परियोजनाओं में जो कार्य चले हये हैं उनका केंद्रीय सहायता के बिना पूरा होना संभव नहीं होगा। यह तथ्य भी इन चुनावों को प्रभावित करेगा ऐसा माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक प्रतिशत से भी कम अन्तर से हारी है। सुक्खू सरकार के पहले बजट सत्र में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका काफी प्रभावी निभाई है। नेता प्रतिपक्ष सदन में काफी आक्रामक रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संयोग रहा है कि सुक्खू सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे ही दिन पिछले छः माह के फैसले पलटकर ऐसा मुद्दा भाजपा को थमा दिया जिससे वह पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार तक प्रदेश के हर कोने तक ले गयी। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस संद्धर्भ में याचिका भी दायर कर दी गयी है। पूरे बजट सत्र में भाजपा ने इस मुद्दे को काफी भुनाया है। इन सारे मुद्दों के अतिरिक्त सरकार ने गारंटीयों को पांच वर्ष में पूरा करने की बात कहकर विपक्ष को और मुद्दा दे दिया है। तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त तब दी जायेगी जब 2000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा और तब तक बिजली की दरें बढ़ा दी गयी हैं। बिजली के अतिरिक्त निगम क्षेत्रों में पानी और गारवेज कलैक्शन की दरें भी 10% बढ़ाकर भाजपा को मुद्दा थमा दिया है। इस तरह मुद्दों के नाम पर निश्चित रूप से भाजपा का प्रक्ष कुछ मजबूत है। देखना है कि चुनाव में आक्रामकता रहती है या नहीं।

मानवता की सेवा से बढ़कर कोई ईश्वरीय कार्य नहीं:शिव प्रताप शुक्ल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है। सेवा ऐसा भाव है जिसे करने वाला भी सुख पाता है और जिसकी की जाती है वह भी सुख पाता है। यह बात

उन्होंने मण्डी जिले के सुन्दरनगर स्थित डैहर में दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के दौरे के दौरान कही। राज्यपाल बनने के बाद वह पहली बार मण्डी पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने न्यास का दौरा किया और वहां उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज यह संस्थान स्वामी स्वतंत्रानन्द महाराज के दिखाए मार्ग पर कार्य कर रहा है। उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान आज 73 बच्चों का भरण-पोषण एवं शिक्षण का कार्य अपने भवन में ही कर रहा है। पात्र बच्चियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण अपनी उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और फीस से लेकर उनकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हों, इस दिशा में न्यास प्रशंसनीय कार्य कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि इस संस्थान के बच्चे न केवल शैक्षणिक स्तर पर बल्कि अन्य गतिविधियों में भी अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को और बढ़ावा मिलना चाहिए।

इससे पूर्व, ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्य प्रकाश आर्य ने राज्यपाल को सम्मानित किया। उन्होंने न्यास की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान पात्र बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और इस वर्ष यह सहायता करीब 6.16 लाख रुपए की राशि 132 बच्चियों को प्रदान की गई।

इस अवसर पर, संस्थान के बच्चों द्वारा योग व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल, पुलिस अधीक्षक सौम्य सांबशिवन, अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने सुंदरनगर स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष बच्चों के लिए चलाए जा रहे संस्थान का दौरा भी किया। उन्होंने पैरा आलोम्पिक में पदक जीतने वाली संस्थान की दो छात्राओं को सम्मानित भी किया।

संस्थान की प्रधानाचार्य नीलम लगवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी।

शुक्ल ने जिला रेडक्रॉस के माध्यम से सुंदरनगर में संचालित डायलेसिस यूनिट का भी दौरा किया तथा वहां उपचाराधीन रोगियों से बातचीत की।

राज्यपाल ने भंगरोटू स्थित बल्ह वैली कल्याण सभा वृद्धाश्रम का दौरा भी किया। राज्यपाल ने 19 वृद्धों को जिला रेडक्रॉस के माध्यम से सहायता उपकार भी भेंट किये।

वृद्धाश्रम के वरिष्ठ प्रधान डॉ रजनीश ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा वृद्धाश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

राज्य के गरीब पात्र विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा शिक्षा ऋण

शिमला/शैल। संसाधनों की कमी के कारण उच्च और व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ विद्यार्थियों का सपना प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इसमें सहायक बनेगी सरकार की नवोन्मेषी एवं महत्वकांक्षी 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना'।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में गरीब विद्यार्थियों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत सहभागी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से विद्यार्थी यह ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें ट्यूशन फीस, आवास, किताबें एवं शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्च वहन करने में सहायता मिलेगी।

इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पीएचडी, आईटीआई के पाठयक्रम, पॉलिटेक्निक, बी-फार्मेसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) सहित कई व्यवसायिक पाठयक्रम इस योजना में शामिल होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में राज्य में कोई भी गरीब बच्चा उच्च और व्यवसायिक शिक्षा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज दर सिर्फ उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है, ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। राज्य सरकार का संकल्प है कि धन की कमी के कारण कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि योजना को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है।

इस योजना के माध्मय से गरीब विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और उनकी क्षमता का सही उपयोग सुनिश्चित होगा तथा इससे उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में भी मदद मिलेगी। व्यवस्था परिवर्तन करने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना इन्हीं में से एक है।

सरकारी संस्थानों में 18 वर्ष आयु से अधिक की 20 हजार मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर 25 हजार रुपए का उपदान प्रदान करेगी। इससे छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित होंगी, वहीं ई-स्कूटी का उपयोग हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में भी सहायक होगा।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति बचनबद्ध:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं युवा सेवा व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता देने के प्रति बचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का युद्ध स्तर पर विस्तार किया जाएगा।

अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के चनावग में पशु चिकित्सालय औषद्यालय भवन के लोकार्पण व चनावग व नैहरा पंचायत के लिये उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद जिला स्तरीय देव हरसिंग मेले में लोगों को सम्बोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने इस निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने उन्हें भारी मतों से जीताकर फिर से सेवा का मौका देने के लिये आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह ने

प्रदेश के विकास की जो नीव रखी है उसे वह हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिये कृत संकल्प हैं। उन्होंने कहा भले ही वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नही है पर उनका प्यार स्नेह व उनका मार्गदर्शन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और जन सेवा के लिये प्रेरित करता हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं का आहवान किया कि वह अपने क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि पशुधन एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारी आये का बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोत बन सकता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालन को बढ़वा दे रही है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमे पारंपरिक खेती और हरति क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान लोगों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं को दूर करने में किसी भी प्रकार की विलम्ब न करें।

आबकारी विभाग ने 1.10 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण पकड़े

शिमला/शैल। वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामलों के निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान हमीरपुर में लगभग 1.10 करोड़ रुपए के करीब 2 किलोग्राम सोने के आभूषण पकड़े गए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तम्बाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस डीलर द्वारा सिगरेट के कुछेक ब्रांड उपयुक्त दस्तावेजों के बगैर खरीदे गए थे।

आयुक्त ने कहा कि विभाग विशेष तौर पर सोने एवं तम्बाकू पर जीएसटी कर चोरी के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोने एवं चांदी पर जीएसटी की न्यूनतम दर 3 प्रतिशत है जबकि तम्बाकू पर जीएसटी की दर विभिन्न उप-करों सहित 188 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि हालांकि सोने एवं चांदी पर जीएसटी की दर न्यूनतम है परंतु इसकी कीमत अधिक होने के कारण कर चोरों को इससे बड़े स्तर पर मुनाफा हो रहा है। इसी प्रकार जीएसटी की उच्चतम दरों के कारण तम्बाकू उत्पादों पर कर चोरी से भी काफी लाभ होता है। ऐसे में विभाग कर चोरी की लिहाज से इन दोनों पर ही विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग ने माल ढुलाई में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बंधित विभिन्न मामलों में 8 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री द्वारा बागबानों के हित में लिया गया निर्णय ऐतिहासिक:बुशैहरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं प्रवक्ता देवेन्द्र बुशैहरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बागबानों के हित में जो निर्णय लिया वह ऐतिहासिक है। इस निर्णय से भविष्य में अब बागबानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा जिससे उनका खर्च भी बचेगा। यह अपने

आप में एक ऐतिहासिक मिसाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बागवानों के हितों की रक्षा की है। सेब का सीज़न आरम्भ होने से पूर्व यह निर्णय कांग्रेस सरकार की गंभीरता को दर्शाता है व पार्टी के घोषणा पत्र में कहे अपने तीसरे वचन को भी निभाने की दिशा में एक कदम भी है।

जबकि इससे पूर्व पिछली भाजपा सरकार ने न केवल गुम्मा में सेब कार्टन बनाने वाली फैक्ट्री को ही बन्द कर दिया जिसके फलस्वरूप बागवानों को बाहरी राज्यों के सेब पेटी सप्लायरों से घटिया कार्टन जीएसटी कर सहित मंहगे मूल्यों पर खरीदने पर मज़बूर होना पड़ा। भाजपा सरकार ने बागवानों को पेटियों पर सब्सिडी के नाम पर भी धोखा दिया। इसके अतिरिक्त तब की कांग्रेस सरकार के समय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से 1134 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन तब कांग्रेस सरकार बदल गयी लेकिन इस राशि का भाजपा सरकार ने क्या किया इसका जवाब देने में पूरी तरह से विफ़ल रही है। प्रदेश सरकार समय रहते इसका पता करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस सरकार आरम्भ से ही बागवानों की सभी समस्यायों से अच्छी तरह से परिचित है, चाहे वह समस्या कीटनाशकों, खाद, सेब ढुलाई या प्रयाप्त संख्या में उन्हें सेब पेटियों की सप्लाई की क्यों न हो। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार सेब उत्पादकों को यूनिवर्सल टेलिस्कोपिक सेब क्रेट सप्लाई करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

पहले बागवानों को पेटियों के लिहाज से अपने सेब बेचने से नुकसान होता था लेकिन अब किस्म के अनुसार तोलकर बेचने के लिहाज से नए कार्टन में लगभग 24 किलो से अधिक सेब पैक नहीं करेंगे जबकि पहले पेटी में अधिक पैक करने पड़ते थे, उससे बागवानों, फल उत्पादकों को अधिक नुक्सान होता था जबकि नयी प्रणाली से उनको फायदा रहेगा। कांग्रेस सरकार हमेशा बागवानों की हितैशी रही है जबकि भाजपा सरकार ने हमेशा बागवानों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की है।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा ज़िले के बीड़ में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा ज़िले के बीड़ में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त बीड़-बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत भी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं के बेहतर आयोजन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी और यहां लैंडिंग साइट के आसपास भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीड़ में कॉर्निवल आयोजित करने पर विचार करेगी। उन्होंने पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में बैजनाथ में नए तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ बहुतकनीकी संस्थान खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा ज़िला को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा करेगी, जिसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी।

मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं, ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ लीज समाप्त होने के बाद वर्ष 2024 में शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलने जा रहा है।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप में टीम श्रेणी में टीम देव पशाकोट एडवेंचर ने पहला, टीम कारो नेपाल ने दूसरा और टीम नेपाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं इंडियन नेशनल ओपन वर्ग में सोहन ठाकुर पहले, कुमार दूसरे और चित्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में अदिति ठाकुर ने पहला, रीता श्रेष्ठ ने दूसरा और अलीशा कटोच ने तीसरा स्थान हासिल किया। ओवरऑल प्रतियोगिता में चित्र सिंह ने पहला, विशाल थापा ने दूसरा और अमन थापा ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 5 देशों के कुल 103 पायलटों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए स्वामी रामानंद जी चौरिटेबल ट्रस्ट तथा पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने एक-एक लाख रूपए, एचपीएसईबीएल कांगड़ा, पीडब्ल्यूडी डिवीजन बैजनाथ, जल शक्ति विभाग, अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने 51-51 हजार रूपए के चेक भेंट किए।

राज्य में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में विचार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी। भांग में कई औषधीय गुण पाये जाते है। इसके औषणीय गुणों के इस्तेमाल से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें पांच विधायकों को सदस्य बनाया गया है। समिति उन इलाकों का दौरा करेगी, जहां भांग की अवैध खेती होती है। समिति सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भांग की खेती को वैध करने के बारे में सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में भांग की खेती को कानूनी मान्यता दी गई है। वहीं देश के कई राज्यों में भांग की खेती को कानूनी दायरे में रखा गया है। उत्तराखंड वर्ष-2017 में भांग की खेती को वैध करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है। प्रदेश सरकार इन सभी पहलुओं का भी ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर न हो।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत की संसद में वर्ष 1985 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत भांग को परिभाषित किया था, जिसके तहत भांग के पौधे से राल और फूल निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यह कानून औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की विधि और सीमा निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 10 (ए) के अंतर्गत राज्यों को किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, कब्जा, परिवहन, खपत, उपयोग और खरीद तथा बिक्री, भांग की खपत (चरस को छोड़कर) के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। राज्यों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने का अधिकार है।

मजबूत निवेश से सुदृढ़ होगी प्रदेश की आर्थिक

शिमला/शैल। राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के भीतर निवेशकों को एकल छत सुविधा तंत्र के माध्यम से व्यापार में सुगमता और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब को कम करने के लिए प्रदेश में 'निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो' की स्थापना का प्रस्ताव है। यह ब्यूरो हिमाचल को देश का आदर्श निवेश अनुकूल राज्य बनाएगा और निवेशकों को 'प्लग-एंड-प्ले इंटरफेस' प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्य सरकार पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो से न केवल राज्य में निवेश आने से राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि उद्योग क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 90 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे ।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश पर निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो पुरानी एकल खिड़की प्रणाली के स्थान पर कार्य करेगा और इसमें निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां निहित होंगी। इस निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जा रही है और सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से सम्बधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और कार्य में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान भी होगा।

प्रदेश सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने लिए निवेश नीति की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रही है। भविष्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने समग्र निवेश नीति तैयार करके राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे निवेशकों को तीव्र और बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में रेल सम्पर्क और सड़कों के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी। पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा इकाइयों आदि से सम्बंधित इकाइयों पर विशेष बल दिया जा रहा है। पर्यटन और सम्बंधित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है क्योंकि इसमें निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं और लाभ समय-समय पर प्रदान किए जा रहे हैं। ऊना में बल्क ड्रग पार्क और फार्मा सेक्टर के कार्यान्वयन के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए 2110 करोड़ रुपये के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

हिमाचल पुलिस का लापता महिलाओं व बच्चों को ढुंढने के लिये विशेष अभियान

शिमला/शैल। पुलिस विभाग ने हिमाचल प्रदेश में लापता महिला और बच्चों का पता लगाने के लिए मार्च 2023 को एक विशेष अभियान शुरू किया था। जिसमें सभी जिलों में लापता महिलाओं और बच्चों को ढूंढने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस टीमों ने उल्लेखनीय कार्य किया और राज्य में 214 लापता महिलाओं व बच्चों का सफलतापूर्वक पता लगाया है जिसमें 33 बच्चे और 181 महिलाएं शामिल है।

पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डु ने सभी जिला पुलिस अध्यक्ष, उपमंडल पुलिस अधिकारियों, पुलिस थाना व पुलिस चौकी प्रभारियों कि इस अभियान की सफलता के लिये सराहना की है।

इस अभियान के दौरान ढूंढी गयी महिलाओं और बच्चों का आंकड़ा यह है

जिला	01 मार्च 2023 को गुम		मार्च 2023 के दौरान गुम हुए बच्चे		मार्च 2023 के दौरान ढुंढे गए		01 अप्रैल, 2023 को लापता बचे	
	बच्चे	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं	बच्चे	महिलाएं
पुलिस जिला बद्दी	14	137	01	19	00	23	15	133
बिलासपुर	02	31	06	12	06	15	02	28
चंबा	09	44	01	11	03	14	07	41
हमीरपुर	02	11	00	09	01	20	01	00
कांगड़ा	35	301	04	23	04	22	35	302
किन्नौर	04	02	00	02	00	01	04	03
कुल्लु	11	57	02	06	03	12	10	51
लहौल व स्पीति	00	03	00	00	00	00	00	03
मण्डी	06	183	07	28	05	24	08	187
पुलिस जिला नूरपुर	03	10	02	01	03	00	02	11
शिमला	10	69	05	16	04	25	11	60
सिरमौर	20	82	01	06	03	14	18	74
सोलन	02	23	00	07	00	07	02	23
उना	10	36	01	03	01	04	10	35
कुल	128	989	30	143	33	181	125	951

सुख-आश्रय विधेयक, 2023 से होगा अनाथ, निराश्रितों का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही राज्य में लम्बे समय से उपेक्षित मुद्दे को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय (बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 को विधानसभा में पारित करके कानूनी रूप में अनाथ बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया है। इस विधेयक से अनाथ और निराश्रित बच्चों को जहां बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उन्हें अपने भविष्य की नीव को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख-आश्रय (बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता) विधेयक, 2023 के लागू होने से राज्य के 6000 निराश्रित बच्चों, जिन्हें अब 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में अपनाया गया है, के लिए प्रदेश सरकार ही माता और पिता हैं। राज्य सरकार इन बच्चों को अभिभावक के रूप में पालने-पोसने, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरसम्भव प्रयास करेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य अनाथ, निराश्रित और दिव्यांग बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इसमें चाइल्ड केयर और आफ्टर केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों को वस्त्र और उत्सव अनुदान प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही बच्चों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में वार्षिक शैक्षणिक भ्रमण का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार योगदान देगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग की अवधि के दौरान भी उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो बच्चे 18 वर्ष की आयु के बाद अपना स्टार्ट-अप स्थापित करना चाहते हैं, उनको प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा भूमिहीन अनाथों और निराश्रितों को तीन बिस्वा भूमि आवंटन व आवास अनुदान का भी प्रावधान है।

अपने जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीतते हैं, तो आप नेतृत्व कर सकते हैं! यदि आप हारते हैं, तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं! ......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या अगला पड़ाव हिन्दू राष्ट्र होगा

इस समय देश का राजनीतिक परिदृश्य जो आकार लेता जा रहा है उसके परिपेक्ष में हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता जा रहा है कि इस सबका अंतिम परिणाम क्या होगा। यह सब क्यों रहा है? क्या 2024 की सत्ता ही इसका एकमात्र लक्ष्य है या इसके पीछे का मकसद कुछ और है? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए 2014 के चुनाव से पहले उभरे वातावरण पर नजर डालना आवश्यक है। स्मरणीय है कि उस समय विदेशों में काले धन के जो आंकड़े तब परोसे जा रहे थे उसने हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित किया था। इन्हीं आंकड़ों के बीच 2जी स्कैम का 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा आ गया। इस आंकड़े पर देश के प्रधान लेखाकार विनोद राय की मोहर लगी थी। इसलिए इसे पूरा प्रमाणिक माना गया। कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा भी आ गया। और इन सब मुद्दों के परिणाम स्वरुप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आन्दोलन छिड़ गया। अन्ना हजारे इस आन्दोलन के नायक बन गये और लोकपाल की नियुक्ति इसकी प्रमुख मांग बन गयी। अंतिम दिनों में यह आंदोलन किस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ यह सब जानते हैं। यह आन्दोलन आरएसएस का प्रायोजित था यह स्पष्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी और अरविन्द केजरीवाल इसी आन्दोलन के प्रतिफल है।

इसी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में 2014 के चुनाव घोषित हुए भ्रष्टाचार और काले धन के आंकड़े के प्रभाव में ही हर आदमी के खाते में पंद्रह-पंद्रह लाख आने का सपना दिखाया गया। कांग्रेस में काफी तोड़फोड़ हुई और परिणाम स्वरूप सत्ता बदल गयी। सत्ता बदलने के बाद पंद्रह लाख चुनावी जुमला बता दिया गया। जिस 2जी स्कैम में 1,76,000 करोड़ के घपले का आंकड़ा प्रधान लेखाकार विनोद राय ने परोसा था उन्होंने बाद में अदालत में शपथ पत्र देकर यह कहा कि कोई स्कैम नहीं हुआ था गणना करने में गलती लग गई थी। अन्ना आंदोलन में जिस लोकपाल की नियुक्ति प्रमुख मांग थी क्या उसके पास आज तक कोई बड़ा मुद्दा गया है? शायद नहीं। 2014 के चुनाव में जो वायदे किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। लेकिन चुनावी वायदों की ओर ध्यान जाने से पहले ही गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दे प्रमुख हो गये। चुनावी वायदों की जगह नोटबंदी आ गयी जीएसटी आ गया। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना आ गयी। इसमें दिये गये ऋण का कितना हिस्सा वापिस आ पाया है यह आंकड़ा आज तक जारी नहीं हो सका है। 2019 के चुनावों के बाद श्रम कानूनों में किया गया बदलाव किसी चुनाव का वायदा नहीं था और न ही कृषि कानून लाने का कोई वायदा था। यदि कोविड के कारण देश में लॉकडाउन न लगता तो शायद श्रम और कृषि कानूनों पर उभरे आन्दोलन का स्वरूप कुछ और ही होता।

जब यह सब हो रहा था तो इसके समानांतर ही हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए अलग से काम हो रहा था। मेघालय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस.आर.सेन ने यह फैसला दिया कि देश को अब हिन्दू राष्ट्र हो जाना चाहिए। इस फैसले को 2019 में इसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की पीठ ने बदल डाला। लेकिन यह फैसला तो आया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से नया भारतीय संविधान वायरल हुआ। मनुस्मृति आधारित इस कथित संविधान के वायरल होने पर संघ और केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं आज तक नहीं आयी है। संघ हिन्दू राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है यह सब जानते हैं। संघ का मोदी सरकार पर कितना प्रभाव है यह भी किसी से छुपा नहीं है। भाजपा संघ की राजनीतिक इकाई से ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा सरकारों का केंद्र से लेकर राज्यों तक अधिकांश आचरण हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना के गिर्द ही घूमता आ रहा है। इस परिपेक्ष में जब यह परिदृश्य निर्मित होता जा रहा है की पूरी राजनीति भाजपा बनाम विपक्ष की बजाये राहुल बनाम मोदी होने तक पहुंचा दी गयी है। पूरे सरकारी प्रयासों से एक भामाशाह तैयार किया जा रहा है। पूरी सरकार खुलकर उसके बचाव में खड़ी हो गयी है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी कहीं भी चिन्ता और चिन्तन का विषय नहीं रह गये हैं। सत्ता से मतभेद रखने वाला हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी करार दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति को ही अराजकता की संज्ञा दी जाती है। और अराजक वातावरण में ही नये फैसले थोपे जाते हैं। क्या यह सब 2024 की सत्ता से ज्यादा हिन्दू राष्ट्र के ऐजेण्डे को व्यवहारिक रूप देने के लिये एक जमीन तो तैयार नहीं की जा रही है।

भूरी सिंह संग्रहालय चंबा पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र

शिमला। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है । यहां मौजूद कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेज शोधार्थियों और पर्यटकों को ज़िला की समृद्ध परंपरा और गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाने को लेकर भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 14 सितंबर 1908 को हुई। राजा भूरी सिंह 1904 से 1919 तक चंबा के राजा थे। राजा भूरी सिंह ने परिवार के चित्र तथा कई पुरातत्व महत्व की शाही वस्तुएं संग्रहालय को दान किए थे।

वर्तमान में संग्रहालय में छह गैलरियां है जिसमें पुरातत्व गैलरी, लघु चित्र गैलरी और नृविज्ञान गैलरी, काष्ठ कला जैसी अलग-अलग गैलरियां हैं जिसे संग्रहालय में पृथक-पृथक देखा जा सकता है।

संग्रहालय में लगभग 65 सौ से अधिक विभिन्न प्रकार की प्राचीनतम ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित रखी है जो चंबा की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को दर्शाती है। इनमें प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र व पांडुलिपियां जो शारदा, टांकरी, भोटी, गुरुमुखी और फारसी लिपियों में लिखित है।

इसके अलावा लघु चित्र, चंबा रुमाल पहली शताब्दी से 18 वीं शताब्दी तक के प्राचीनतम सिक्के, कलाकृतियां, पहाड़ी गहने और संगीत वाद्ययंत्र आदि सम्मिलित है।

अभी हाल ही में 14 सितंबर 2022 को विश्व प्रसिद्ध भूरी सिंह संग्रहालय ने अपना 114 वां स्थापना दिवस मनाया।

भूरी सिंह संग्रहालय चम्बा के प्रारम्भिक संस्थापक जोन फिलीप वोगल तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। राजा भूरी सिंह के दूरदर्शिल और चम्बा के स्थानीय कलाओं से परिपूर्ण हस्त शिल्पों के उत्पादों के संयोजन से इस संग्रहालय की स्थापना का आधार स्थापित किया गया।

यह संग्रहालय भारत की प्रारम्भिक संग्रहालयों में से एक है। यह एक क्षेत्रीय संग्रहालय है। वर्तमान में इस संग्रहालय में प्रयटकों के लिए 6 गैलरियां बनाई गयी हैं।

पहली पुरातत्व गैलरी में पूरे चम्बा रियासत से लायी गयी पाषाण प्रतिमाएं व मन्दिरों मे प्रयोग होने वाले प्रस्तर कला के नमूनें रखे गए है। जो दूसरी शताब्दी ई0 पूर्व से बीसवीं शताब्दी तक के काल व कला को दर्शाते है और पनघट शिलाएं इस गैलरी की शोभा बढाती है।

दूसरी चंबा गैलरी की बात करें तो वे अपने आप में एक लघु संग्रहालय हैं। जिसमें लघु चित्र राजाओं के अस्त्र- शस्त्र, विदेशी मेहमानों द्वारा भेंट की गये बेश कीमती उपहार, रंगमहल से लायी गयी चित्रित दीवारें व दरवाजे तथा एक हजार वर्ष पुरानी देवदार की लकड़ी से बनाई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी गयी है। साथ ही यहां पर्यटकों के देखने के लिए विश्वप्रसिद्ध चम्बा रूमाल भी रखा गया है। तीसरी लघु चित्र गैलरी में 17 वीं शताब्दी सें लेंकर 20 वीं शताब्दी तक के विभिन्न कलाकारों द्वारा चित्रित चित्र देख सकते हैं । भूरी सिंह संग्रहालय न केवल पूरे भारत अपितु विश्वभर में लघु चित्र शैली के चित्रों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है।

भूरी सिंह संग्रहालय के प्रथम तल पर ऐतिहासिक दस्तावेज गैलरी है जहां आप प्रस्तर, पत्थर, धातु, कागज पर विभिन्न लिपियों में लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज को देख सकते हैं।

स्थानीय राजाओं द्वारा मुगल दरबार हो या पड़ोसी राजाओं के साथ जमीन से लेकर सहमति के हर प्रकार के दस्तावेज इस गैलरी में देखने को मिलते हैं इस गैलरी की विशेषता 950AD का युगाकर बर्मन का ताम्रपत्र है जो संग्रहालय का प्राचीनतम ताम्रपत्र है । इसके अलावा इस गैलरी में 1000 वर्ष पुरानी सराहन पुस्ती भी देख सकते हैं। वहीं द्वितीय तल में पर्यटकों के देखने के लिए नृशास्त गैलरी है जिसमें लोग प्राचीन कला के दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुओं को देख सकते हैं चांदी से जड़ित हाथी का हौदा किस गैलरी में चार चांद लगाता है इस गैलरी में चंबा के सभी प्रकार के वचनों को देख सकते हैं

छठी मुद्रा शास्त्र गैलरी मौर्य काल से लेकर आधुनिक भारत के सभी प्रकार के मुद्राओं का अवलोकन कर सकते हैं इस गैलरी के प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के सभी प्रमुख शासकों की मुद्राओं का संकलन किया गया है।

इन सभी के अलावा संग्रहालय में लघु चित्र प्रदर्शनी कक्ष और चंबा के प्राचीन छायाचित्र भी अंकित किए गए हैं।

संग्रहालय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और तकनीकी सहायक सुरेंद्र ठाकुर बताते है कि भूरी सिंह संग्रहालय भारत के प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक है जिसकी स्थापना तत्कालीन पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जॉन फिलिप फॉगल ने 1908 में की थी जो राजा भूरी सिंह के आग्रह पर चंबा आए थे। उन्होंने चंबा विरासत की संस्कृति को देखकर राजा को यह सुझाव दिया था कि क्षेत्र में एक संग्रहालय होना जरूरी है जिसमें इन प्राचीनतम धरोहर वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सके। इस संग्रहालय में दूसरी शताब्दी से लेकर आज तक की वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि यह संग्रहालय अपने आप में एक अनूठा है जिसमें उत्तर भारत के सभी संग्रहालयों में से पहाड़ी मनैचर पेंटिंग का संग्रह भूरी सिंह संग्रहालय में सबसे अधिक है। भूरी सिंह संग्रहालय में वर्तमान में प्रयटकों के लिए 6 गैलरियां है। बताया कि गत 4 वर्षों में संग्रहालय में दो नई गैलरियां स्थापित की गयी है जिसमें जिसमें मुद्रा और नृविज्ञान गैलरी शामिल है।

उन्होंने बताया कि हर वर्ष देश विदेश से 30 से 35 हजार पर्यटक इस संग्रहालय को देखने आते हैं। हिमाचल प्रदेश और जिला चंबा की पारंपरिक और विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए संग्रहालय हमेशा प्रयासरत है।

आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया, महंगाई के खिलाफ जंग जारी रखनी होगी:आरबीआई गवर्नर

शिमला। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य अपने यू ट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सूचित किया कि मौद्रिक नीति समिति ने तत्परता से कार्य करने के साथ सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है, यदि स्थिति के अनुसार कार्य करना आवश्यक हो। नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर बिना किसी बदलाव के 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत रहेगी।

गवर्नर का मानना है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर है और इसके वर्तमान स्तर को देखते हुए, वर्तमान नीतिगत दर को अभी भी उदार माना जा सकता है। इसलिए, एमपीसी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

यह देखते हुए कि वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है, गवर्नर ने बताया कि 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत, पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

गवर्नर ने सूचित किया कि सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.2 प्रतिशत पर मध्यम रहने का अनुमान है, पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत(और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।?

आरबीआई गवर्नर ने पांच अतिरिक्त उपायों की घोषणा की, जैसा कि नीचे दिया गया है।

एक ऑनशोर नॉन-डिलीवरेबल डेरिवेटिव मार्केट विकसित करना

गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (आईबीयू) वाले बैंकों को पहले अप्रवासियों और आईबीयू वाले अन्य पात्र बैंकों के साथ भारतीय रुपये (आईएनआर) में गैर-वितरण योग्य विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (एनडीडीएस) में लेनदेन करने की अनुमति थी।

अब, आईबीयू वाले बैंकों को एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें ऑनशोर मार्केट में निवासी उपयोगकर्ताओं के लिए आईएनआर शामिल होगा। गवर्नर ने सूचित किया कि यह उपाय भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को और मजबूत करेगा और निवासियों के वित्तीय हानि से बचाव के वायदे को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

नियामक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सूचित किया कि संस्थानों को रिज़र्व बैंक से लाइसेंस/प्राधिकार देने या विनियामक मंजूरी लेने के लिए आवेदन करने के लिए 'प्रवाह' (नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकार देने के मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केन्द्रीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 2023-24 की घोषणा की तर्ज पर, यह वर्तमान प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करेगा, जहां ये एप्लीकेशन आवेदन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगी।

गवर्नर ने सूचित किया कि पोर्टल मांगे गए आवेदनों/अनुमोदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा दिखाएगा। यह उपाय नियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाएगा और रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा।

बिना दावे की जमाराशियों को खोजने के लिए जनता के लिए केन्द्रीकृत वेब पोर्टल का विकास

गवर्नर ने कहा कि वर्तमान में बैंकों में 10 वर्ष या उससे अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि के जमाकर्ताओं या लाभार्थियों को ऐसी जमा राशि का पता लगाने के लिए कई बैंकों की वेबसाइटों के माध्यम से जाना पड़ता है।

गवर्नर ने कहा, अब, इस तरह की बिना दावे की जमाराशियों के बारे में जमाकर्ताओं/लाभार्थियों की पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एक वेब पोर्टल विकसित किया जाए ताकि संभावित दावा न की गयी जमाराशियों की विभिन्न बैंकों में खोज की जा सके। इससे जमाकर्ताओं/लाभार्थियों को दावा नहीं की गयी धनराशि वापस पाने में मदद मिलेगी।

क्रेडिट संस्थानों द्वारा क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गयी क्रेडिट जानकारी से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र

यह याद करते हुए कि क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को हाल ही में रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के दायरे में लाया गया था, गवर्नर ने घोषणा की कि निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

क्रेडिट सूचना रिपोर्ट के अपडेट / सुधार में देरी के लिए एक मुआवजा तंत्र

ग्राहकों की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंचने पर उन्हें एसएमएस/ईमेल अलर्ट का प्रावधान

ऋण संस्थाओं से सीआईसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल करने की समय-सीमा

सीआईसी द्वारा प्राप्त ग्राहक शिकायतों का खुलासा

गवर्नर ने कहा कि ये उपाय उपभोक्ता संरक्षण को और बढ़ाएंगे।

यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन का संचालन

गवर्नर ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में खुदरा भुगतानों को बदल दिया है और याद दिलाया कि कैसे समय-समय पर नए उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई की मजबूती का लाभ उठाया गया है। गवर्नर ने घोषणा की कि अब यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

महंगाई के खिलाफ जंग जारी रखनी है

गवर्नर ने जोर देकर कहा कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। 'हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुद्रास्फीति के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हम लक्ष्य के करीब मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट नहीं देख लेते। हमें विश्वास है कि हम मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को लक्ष्य दर तक नीचे लाने के लिए सही रास्ते पर हैं।'

गवर्नर ने बताया कि भारतीय रुपया कैलेंडर वर्ष 2022 में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है और 2023 में भी ऐसा ही बना रहेगा। यह घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल की ताकत और वैश्विक स्पिलओवर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे बाहरी क्षेत्र के संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार 21 अक्तूबर, 2022 को 524.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पलट गया है और अब हमारी आगे की परिसंपत्ति को ध्यान में रखते हुए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

'हम मूल्य स्थिरता की कोशिश में दृढ़ और कृतसंकल्प हैं'

अंत में, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2020 की शुरुआत से, दुनिया अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, भारत का वित्तीय क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार(मुद्रास्फीति में अपेक्षित नरमी(पूंजीगत व्यय पर ध्यान देने के साथ राजकोषीय समेकन(चालू खाता घाटे को और अधिक स्थायी स्तरों तक महत्वपूर्ण रूप से कम करना(और विदेशी मुद्रा भंडार का सहज स्तर स्वागत योग्य घटनाक्रम हैं जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेंगे।' गवर्नर ने जोर देकर कहा कि प्रमुख मुद्रास्फीति के साथ, हम मूल्य स्थिरता की अपनी कोशिश में दृढ़ और कृतसंकल्प हैं जो दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे अच्छी गारंटी है।

'संजीवनी': पशुधन देखभाल में एक अनूठी पहल

घर-द्वार पर मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं बस एक फोन कॉल दूर

शिमला । कृषि पर आधारित हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक प्रमुख घटक है। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है और इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पशुधन की समय पर उचित देखभाल और पशुपालकों की आजीविका में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने की दिशा में एक नई पहल की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कि पशुधन को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जाए और पशुपालकों को पशु औषधालयों पर जाने और गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाने जैसे अतिरिक्त खर्चों से बचाया जाए। इस उद्देश्य से प्रदेश में 'संजीवनी' परियोजना आरंभ की जा रही है।

वर्तमान में प्रदेश में पशुधन के लिए कृत्रिम गर्भाधान, दवाएं, टीकाकरण, सर्जरी, बांझपन परीक्षण इत्यादि पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनका लाभ उठाने या उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं को निकटतम पशु औषधालयों में ले जाना पड़ता है। इससे यात्रा और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च होता है। कई बार समय पर उपचार के अभाव में पशु बीमार होकर दम तोड़ देते हैं। ऐसे में प्रदेश में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह क्लीनिक किसानों के घर-द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे।

पशुपालन विभाग ने 'संजीवनी' परियोजना के लिए इंडसइंड बैंक की सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम-पशुपालन विभाग- मोबाइल पशु चिकित्सा वैन (एनएडीसीपी-एएचडी-एमवीयू) के तहत 'संजीवनी' परियोजना घर-घर तक पशुधन देखभाल सुविधा सुनिश्चित करेगी और विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं सिर्फ एक फोन कॉल पर उपलब्ध होंगी।

परियोजना के तहत पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए निदेशालय स्तर पर एकीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह कॉल सेंटर पशुपालकों को टेली- मेडिकल-परामर्श, सरकारी योजनाओं की जानकारी, विशेष रूप से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, शिकायत निवारण, प्रश्न-समाधान आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा।

इसके अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में स्थित 44 खंडों में किसानों को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में केंद्रीकृत कॉल सेंटर को इन 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ एकीकृत किया जाएगा। कॉल सेंटर मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक वाहन और कार्यरत पशुधन क्लीनिक के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। इससे पशु औषधालयों तक जाने और बीमार पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने पर किसानों का अतिरिक्त खर्च व समय बच सकेगा।

पशु चिकित्सा सेवाओं में उपचारात्मक सेवाएं, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, निवारक देखभाल और पशुपालन से संबंधित सभी जानकारी घर-द्वार पर उपलब्ध होंगी। एकीकृत टेलीमेडिसिन और सेवा प्रबंधन मंच के माध्यम से पशुपालन विभाग की फील्ड पशु चिकित्सा सेवाओं को तैनात किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से पशु चिकित्सकों और किसानों को आपस में जोड़ेगा। मोबाइल ऐप सेवा वितरण, निर्धारित दवाओं और पशुओं की बीमारियों से संबंधित डेटा की दक्षता को भी ट्रैक करेगा। पशु चिकित्सा सेवाओं के अलावा किसानों को उनके पशुओं के लिए पोषण देखभाल पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

'संजीवनी' परियोजना पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक किसान-हितैषी पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित होगी। विशेषतौर पर छोटे डेयरी किसानों को घर-द्वार पर समग्र रूप से पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में यह एक गतिशील मंच साबित होगा।

मुख्यमंत्री की नई सोच से युवाओं के लिए सृजित होंगे स्वरोजगार के नए अवसर

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नई सोच से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के अतिरिक्त मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा और ई-वाहन जैसे तेजी से उभरते नवीन क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं।

युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने की कांग्रेस सरकार की गारंटी को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना' की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ-साथ डेंटल क्लीनिक में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयों, ई-टैक्सी तथा एक मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल एक सशक्त एवं पर्यावरण हितैषी नीति को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदृष्टि एवं युवाओं के प्रति नई सोच के साथ इसे स्वरोजगार से जोड़ने की पहल भी की है। सौर ऊर्जा उत्पादन को पंचायत स्तर तक ले जाने और इस क्षेत्र में हिमाचली युवाओं को प्रोत्साहन इस बार के हरित बजट की विशेषता है।

प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज़ पर ली गयी भूमि पर 250 किलोवाट से दो मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।

ऊर्जा सक्षम बनने के साथ-साथ राज्य में विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देते हुए इसे भी युवाओं के लिए स्वरोजगार के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। ई-वाहन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत निजी बस एवं ट्रक ऑपरेटरों को ई-बस व ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये का उपदान दिया जाएगा। ई-टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सरकार ने सभी वर्गों के लिए समान रूप से 50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है। चिन्हित बस रूटों पर युवाओं को ई-वाहन चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। निजी संचालकों को ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपदान प्रदान किया जाएगा।

हिमाचल के जलाशयों एवं नदियों को ऊर्जा उत्पादन, जलापूर्ति आवश्यकताओं से एक कदम आगे बढ़ते हुए मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के सशक्त प्रयास भी इस बजट में नजर आते हैं। आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा युवाओं को प्रोत्साहन के दृष्टिगत मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत उपदान की घोषणा की गई है। इस क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज़ कल्चर इत्यादि नई तकनीकों के माध्यम से युवाओं को मत्स्य पालन में आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री हिमाचल को निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव ला रहे हैं। निवेश आने से रोजगार भी पैदा होगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करते हुए लगभग 90 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बजट में 'मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा' आरंभ करने की भी घोषणा की गयी है। इससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं को राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में 25 हजार विभिन्न कार्यशील पदों को भरने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। जल शक्ति विभाग में भी 5000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार व विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र में प्रदत्त रोजगार प्रदान करने की गारंटी को मूर्त रूप प्रदान करने में यह कदम सार्थक सिद्ध होंगे।

हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्यः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल सोशल बॉडीज़ फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम' में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम् योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए कृतसंकल्प है और आगामी चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसे 'पर्यटन राजधानी' घोषित किया गया है और क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों एवं निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गयी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भू-जोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने इस अवसर पर संगठन के साथ अपने गहन लगाव को याद किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के समर्पण और हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और समाज कल्याण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण अनुकरणीय है।

उन्होंने अपने दिवंगत पिता और पूर्व मंत्री जी.एस. बाली को सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फेडरेशन द्वारा प्रदत्त 'हिमाचल रत्न' पुरस्कार भी ग्रहण किया।

हिमाचल सोशल बॉडीज़ फेडरेशन के अध्यक्ष के.आर.वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और फेडरेशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डी.एस. नेगी सहित चार अन्य हस्तियों चुन्नी लाल कौशल, जे.सी. शर्मा, कुमारी अंजलि शर्मा और प्रणव चंदेल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 'हिमाचल गौरव' पुरस्कार भी प्रदान किए।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया।

विकास कार्यों के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी

शिमला/शैल। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी है। इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 34.29 करोड़ रुपये, विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 12.37 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत 2.20 करोड़ रुपये और प्रदेश के 10 जिलों के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत 26.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, पांगी और भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों को विधायक विकास निधि के तहत 5.62 करोड़ रुपये और विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 2.07 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं के अंतर्गत विकास गतिविधियों के लिए चार तिमाहियों में धनराशि जारी करती है, जिसे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के परामर्श पर खर्च किया जाता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है और उसी के अनुसार पहली किस्त जारी की जा चुकी है। बजट में विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाकर 13 लाख किया गया है और विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है और वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समुचित उपाय कर रही है। लोगों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। सही निर्णय और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश अगले दस वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा। सरकार ने विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे प्रदेश की आर्थिकी में धन का प्रवाह बढ़ेगा।

बेटियों को सम्पत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में सरकार का निर्णायक कदम

शिमला/शैल। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने 'हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972' ('हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972') में संशोधन किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से अब पैतृक सम्पत्ति में वयस्क बेटी (विवाहित और अविवाहित) को भी एक अलग इकाई (150 बीघा भूमि तक) माना जाएगा। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 4 में 'पुत्र' शब्द के बाद 'या पुत्री' शब्द सम्मिलत कर त्रुटि को सही किया है।

इस संशोधन के उपरांत बेटी को बेटे के समान एक अलग इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले, इस अधिनियम में एक वयस्क पुत्र को अलग इकाई के रूप में अतिरिक्त 150 बीघा भूमि तक का प्रावधान था जबकि वयस्क पुत्री को इस समान अधिकार से वंचित रखा गया था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर प्रदेश विधानसभा में 29 मार्च, 2023 को यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हुए 3 अप्रैल, 2023 को इसे पारित कर दिया गया। इससे पैतृक सम्पति में पुत्र और पुत्री दोनों को ही स्वतंत्र इकाई मानते हुए लैंगिक समानता सुनिश्चित की गयी है।

यह विधेयक भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लैंगिक असमानता को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय में विशेष रूचि दिखाते हुए राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने की पहल की। प्रदेश सरकार के इस कदम का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत करते हुए इसे राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल करार दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक संशोधन कर पुत्रियों वाले लाखों परिवारों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खंडों को हटाकर बेटियों को पैतृक सम्पत्ति के भू-स्वामित्व में समान अधिकार सुनिश्चित करना है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 1135 लीटर अवैध शराब पकड़ी

शिमला/शैल। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, युनूस ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के विरूद्ध अभियान में शिमला और आबकारी ज़िला बद्दी में आबकारी अधिनियम उल्लंघन के अंतर्गत कारवाई करते हुए विभाग ने 5,19,440 रुपए मूल्य की 1135 लीटर अवैध शराब पकड़ी है।

आबकारी ज़िला बीबीएन बद्दी के सहायक आयुक्त आबकारी प्रेम कैथ के नेतृत्व में एक टीम ने क्षेत्र के 15 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 29 और एक बीयर की पेटी जब्त की है। इन मामलों में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कारवाई अमल में लायी जाएगी।

उन्होंने बताया कि ज़िला शिमला में एएसटीइओ रोहड़ू आदर्श शर्मा ने विशेष जांच यूनिट शिमला के साथ चिड़गांव के एक ढाबे और एक बार में दो मामले दर्ज किए हैं। बार में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 50 पेटियों और देसी शराब की 30 पेटियों का अतिरिक्त भण्डारण पाया गया। चिड़गांव में सड़क किनारे एक ढाबे में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 3.5 पेटी तथा देसी शराब की एक पेटी पकड़ी गयी। इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

आईजीएमसी शिमला व मेडिकल कॉलेज टांडा में छह माह में आरंभ होगी रोबोटिक सर्जरी सुविधाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले छह माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव द्वारा 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि प्रदेश में ही मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इससे लोगों के समय और धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां 134 प्रकार की प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारी, नवीनतम अत्याधुनिक एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की आधारभूत संरचना को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉ.राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' खोला जाएगा। कैंसर विभाग के लिए 400 करोड़ रुपये और 150 बिस्तरों की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य मशीनरी और उपकरणों से लैस करेगी और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान भी किया जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार), गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, वित्त सचिव अक्षय सूद, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के आग्रह पर विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंची बालिका आश्रम की बच्चियां

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का अनाथ बच्चों के प्रति स्नेह एक बार पुनः

देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर बालिका आश्रम टूटीकंडी के 69 बच्चे विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे। इन बच्चों ने पहली बार विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही देखी।

विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे बच्चे बहुत खुश व उत्साहित नजर आये। बाद में इन बच्चों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दोपहर भोज का आनंद भी लिया।

मुख्यमंत्री प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय जाने की बजाय बालिका आश्रम जाकर उनसे बातचीत की। प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' आरंभ की है, जिसके लिए 101 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कोष के लिए अपना एक माह का वेतन दिया है, जबकि सभी कांग्रेस के विधायकों ने एक-एक लाख रुपये का अंशदान दिया है।

नौतोड़ मामलों का सर्वमान्य हल सुनिश्चित करेगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार किन्नौर जिले में नौतोड़ भूमि मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर इसका सर्वमान्य समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने किन्नौर वेलफेयर सोसायटी के कार्यक्रम 'तोशिम-2023' को संबोधित करते हुए कहा कि किन्नौर जिला अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है और वर्तमान राज्य सरकार

जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में 10 सीए (नियंत्रित वातावरण) स्टोर स्थापित कर रही है ताकि उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विभाग ने इन सीए स्टोरों की स्थापना के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए किन्नौर जिले में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। इस स्कूल का परिसर 40 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्कूल राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे, जो विद्यार्थियों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से हरित बजट पेश किया है। सरकार दीर्घकालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत हरित ऊर्जा और हरित अमोनिया के उत्पादन की दिशा में प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है और सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय विधेयक-2023 को वर्तमान विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया है। इससे राज्य के लगभग 6000 अनाथ सम्मानजनक तरीके से जीवन-यापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में गोद लिया जाएगा। इसके अंतर्गत 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए बॉक्सर मीनाक्षी नेगी और जम्मू-कश्मीर में कार्यरत प्रधान आयुक्त (जीएसटी) हीर भगत नेगी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने मुक्केबाजी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मीनाक्षी नेगी को एक लाख का पुरस्कार की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने स्मारिका का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर किन्नौर वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष के लिए 1.11 लाख की राशि का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक लाख रुपये की घोषणा की।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत राज्य में व्यवस्था में सुधार के उनके प्रयासों की सराहना की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, कांग्रेस नेता पुष्पिंदर वर्मा, पूर्व मुख्य सचिव वी.सी.फारका, अन्य पदाधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन गौरव की बातः बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर एस बाली ने 5 से 9 अप्रैल तक आयोजित होने वाली एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप 2023 का शुभारंभ। मुख्य संसदीय सचिव एवं बैजनाथ

के विधायक किशोरी लाल इस अवसर पर विशेष रूप में उपस्थित रहे।

एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप 2023 कटागिरी-दो में कुल 142 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इस प्रतियोगिता में 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भारत सहित अमेरिका, नेपाल स्पेन और नीदरलैंड के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 95 पुरुष जिसमें 74 भारतीय और 21 विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं। जबकि महिलाओं में 8 प्रतिभागी हैं जिसमें पांच भारतीय और 3 प्रतिभागी विदेशी हैं। प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 10 नौसेना से एक, वायु सेना के एक तथा पैरामिलिट्री फोर्स के 5 प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं।

प्रतियोगिता से पूर्व आर एस बाली ने प्रतियोगिता के सफलता पूर्वक आयोजन एवं पायलट्स की सुरक्षा के लिए रखे गये हवन में पूर्ण आहुति डाली। उन्होंने हरी झंडी देकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

बाली ने कहा कि बीड़-बिलिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन इलाके, प्रदेश और देश के लिये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिये अपनी विशेषताओं के चलते दुनियांभर की सर्वश्रेष्ठ जगहों में आंकी जाती है। उन्होंने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की बधाई दी और सफलता पूर्वक आयोजन के लिये सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एसोसिएशन को बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड कप के आयोजन के लिये भी सभी मापदंड पूरे करने के प्रयास करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं और बीड़ में ऐरो स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण भी पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 12 करोड़ से किया गया था ताकि इस क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग के बजट में 10 गुणा वृद्धि कर वार्षिक बजट को 50 करोड़ से साढ़े 500 करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्यों नहीं आ पाया प्रदेश की आर्थिकी पर श्वेत पत्र उठने लगा है सवाल

श्वेत पत्र न ला पाना सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र समाप्त हो गया और इस सत्र में यह सरकार प्रदेश की आर्थिकी पर श्वेत पत्र नहीं ला पायी है। जबकि ऐसा आश्वासन प्रदेश की जनता को दिया गया था। क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी पूर्व जयराम सरकार पर प्रदेश को कर्ज के गर्त में डुबाने का आरोप लगाती थी। बल्कि उस समय भी प्रदेश की आर्थिकी पर श्वेत पत्र की मांग करती थी। अब जब स्वंय सत्ता में आ गयी तो पहले दिन से ही प्रदेश की जनता को यह बताया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति नाजुक है। 75000 करोड़ का कर्ज और 11000 करोड़ की देनदारियो विरासत में मिलने का आंकड़ा जनता के सामने रखा गया। पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुये यहां तक आशंका व्यक्त की गयी कि प्रदेश के हालत कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। जब इस आशंका पर सवाल उठे तो यह कहा गया कि सरकार वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करेगी। यह श्वेत पत्र जारी करने के लिए नयी सरकार के पहले बजट सत्र से ज्यादा अनुकूल अवसर और विधानसभा पटल से बेहतर और कोई मंच नहीं हो सकता। लेकिन सरकार यह श्वेत पत्र ला नही पायी है और अगले किसी भी सत्र में इसे लाने का कोई औचित्य नहीं होगा। क्योंकि तब तक इस सरकार के अपने खर्चों और लिये जा रहे कर्ज पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे।

सुक्खू सरकार ने जब श्रीलंका जैसी आशंका जताई थी तब इस पर कुछ सवाल भी उठे थे। लेकिन अब जब वर्ष 2023-24 का बजट पेश होकर पारित भी हो गया है और वर्ष 2021-22 कि कैग रिपोर्ट भी सदन पर आ गयी है तो इनके आंकड़ों और खुलासों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। सरकार ने कर्ज का आंकड़ा 75000 करोड़ बताया है इसमें यह भी बताया है कि इस ऋण का 30% से भी अधिक अगले तीन वर्षों में लौटाया जाना है। यह भी बताया गया है कि केन्द्र से जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है इसलिये केंद्रीय ग्रान्ट में भी कटौती होगी। 2023-24 के बजटीय आंकड़ों में विकासात्मक राशि उतनी ही है जितनी 2022-23 में थी। राजस्व खर्चों में केवल आठ सौ करोड़ की बढ़ौतरी है। आंकड़ों के इस परिदृश्य में स्पष्ट है कि जो भी वायदे यह सरकार करके आयी है उनकी आंशिक प्रतिपूर्ति के लिये भी सरकार को पहले से ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। यह वित्तीय स्थिति एक कड़वा सच है जिसे किसी भी लीपापोती से छिपाया नहीं जा सकता। क्योंकि तीन वर्षों में 30% से भी अधिक के कर्ज की भरपायी और गारंटियां पूरी करने में ठोस कदम उठा पाना कर्ज और पिछले दरवाजे से कर लगाये बिना संभव नहीं हो सकेगा। यही सरकार की सेहत के लिये भारी पड़ेगा।

सरकार भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों पर अभी सूचना ही एकत्रित कर रही है

ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि यह सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं ला पायी। प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन के लिये चयनित सरकार और उसके मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सचिव वित्त की होती है। क्योंकि वह स्थायी कार्यपालिका का सदस्य होता है उसे चयनित सरकार के बाद भी रहना होता है। यह सही है कि कार्यपालिका के यह अधिकारी चयनित सरकार का अपने में एक आकलन कर लेते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। अपने बचाव के लिये इन्होंने एफआर बी एम में ऐसा संशोधन कर रखा है कि किसी भी वित्तीय आकलन की असफलता के लिये इनके ऊपर को आपराधिक जिम्मेदारी आयत नहीं होती। स्वभाविक है कि जब सरकार पहले दिन से ही वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप पूर्व सरकार पर लगाने लग गयी थी तो श्वेत पत्र के माध्यम से यह लोग ऐसा कुछ भी सदन के पटल पर क्यों आने देते। इस धारणा की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि सदन में चार अप्रैल को विधायक यादविंदर गोमा का प्रश्न था कि ऐसे कितने अधिकारी /कर्मचारी है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या सरकार आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों को उन विभागों से हटाने तथा उन पर कारवाई करने का विचार रखती है। इसके उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना किस अधिकारी से शुरू होती है पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन सरकार ने यह सूचना सदन के पटल पर न लाकर यह स्पष्ट कर दिया है की भ्रष्टाचार को लेकर उसका क्या रुख रहने वाला है। स्पष्ट है कि अधिकारी सरकार पर भारी पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सदन के पटल पर श्वेत पत्र न रखकर सरकार ने अपनी ही विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर लिया है।

घटती जा रही है केंद्रीय सहायता तीन वर्षों में मिले 55150 करोड़

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार से वस्तु एवम् सेवा कर क्षतिपूर्ति बंद हो चुकी है। यह क्षतिपूर्ति बन्द होने के बाद इसके बदले में केन्द्र सरकार प्रदेश को कर्ज देकर सहायता कर रही है। केन्द्र से प्रदेश को वित्तायोग अनुदान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुदान, केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान और ऋण के रूप सहायता मिलती है। प्रदेश में पूंजीगत निवेश के लिये दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। पूंजीगत निवेश विकास कार्यों पर लिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इन मदों में मिलने वाली सहायता का आकार लगातार घटता जा रहा है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह सहायता नहीं के बराबर रह जायेगी। ऐसी वस्तु स्थिति की ओर क्या प्रदेश का ध्यान अभी से नही जाना चाहिये? क्योंकि सरकार के बहुत से विभागों में 80% कार्य बाह्य पोषित योजना के सहारे ही चल रहे हैं।

पिछले दिनों प्रदेश और केन्द्र में एक ही दल की सरकार रही है। फिर इस सहायता का आकार लगातार घटता गया है। ऐसे में अब सुक्खु सरकार को केन्द्र से कितनी सहायता मिल पायेगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस परिदृश्य में गारंटीयों की दिशा में सरकार टैक्स लगाने और कर्ज लेने के अतिरिक्त कैसे कदम बढ़ा पायेगी आने वाले दिनों में यह बड़ा सवाल होगा। क्या इस वस्तु स्थिति में प्रदेश मुख्य संसदीय सचिवों जैसे पदों को पोषित कर पायेगा?

यह है तीन वर्षों में मिली सहायता

गत तीन वर्षों में दिनांक 31.01.2023 तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई; ब्यौरा दें?

गत 3 वर्षों {2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (दिनांक 31.01.2023 तक)} में केन्द्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता का ब्यौरा :–

(राशि करोड़ में)

	मद	प्राप्त आर्थिक सहायता			
1. अनुदान		2020–21	2021–22	2022–23 (31.01.2023 तक)	कुल सहायता
क	वित्तायोग अनुदान	12424	11044	8639	32107
ख	बाह्य सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत अनुदान	556	831	598	1985
ग	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान	3665	4590	2389	10644
घ	अन्य	3484	3863	1265	8612
	योग (क+ख+ग+घ)	20129	20328	12891	53348
2. ऋण					
क	बाह्य सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण	62	92	66	220
ख	पूंजीगत निवेश हेतु ब्याज मुक्त दीर्घकालीन ऋण	533	800	249	1582
	योग (क+ख)	595	892	315	1802
	कुल योग(1+2)	20724	21220	13206	55150